इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 02 सितम्बर 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग-से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------4
विनियामकों के कथन ----------4
सूक्ष्मवित्त ----------5
विदेशी मुद्रा----------5
बीमा----------5
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 6
शब्दावली ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

बासेल III मानदंड

13 सितम्बर, 2010 को वैश्विक विनियामकों द्वारा यथासहमत बैंकों की पूंजी से सम्बन्धित नये नियमों से विश्व के बैंकों को राहत महसूस हुई है। बासेल III के रूप में ज्ञात इन नयी आवश्यकताओं के तहत बैंकों से उनकी जोखिमपूर्ण परिसम्पत्तियों के कुल 7% जितनी श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली पूंजी धारित करना अपेक्षित होगा। नये पूंजी अनुपात में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ 2% की वर्तमान अपेक्षा में पर्याप्त वृद्धि का निरूपण शामिल है ।

- ये जोखिम का आकलन और जोखिमों के साथ पूंजी का सम्बन्ध निर्धारण करने हेतु बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) द्वारा निर्धारित (लिखित) नियम हैं।

- पूंजी के मुख्य घटक सामान्य इक्विटी और प्रतिधारित अर्जन हैं।

- टियर 1 पूंजी, जिसमें सामान्य इक्विटी और शाश्वत अधिमानी स्टॉक का समावेश होता है, को जनवरी 2013 से प्रारंभ करते हुए जनवरी 2015 में समाप्त होने वाले चरणों में 2% से बढ़ाकर 4.5% किया जाएगा।

- इसके अलावा, बैंकों को भावी दबाव के लिए आकस्मिकता के रूप में 2.5% की एक अन्य रकम भी अलग रखनी होगी।
- नये मानदंड केन्द्रीय बैंकरों द्वारा स्थूल विवेकसम्मत स्थिरता पर नवीकृत संकेन्द्रण पर आधारित हैं, क्योंकि वैश्विक विनियामकों ने किसी एक बैंक का सूक्ष्म विनियमन करने की बजाय समग्र प्रणाली की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का निश्चय किया है।

- नये नियमों से भारतीय बैंकों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात 9.3% टियर 1 पूंजी सहित 13.4% है।

- टियर I और टियर II पूंजी से कुछेक कटौतियों के सामान्य इक्विटी में स्थलांतरित किए जाने के फलस्वरूप कुछेक नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में कारबार संपर्कियों ने अधिकतम खाते खोले

केन्द्र द्वारा (ग्रामीण जन-समुदाय को बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय समायोजन योजनाओं के एक अंग के रूप में) आरंभ किए गए कारबार संपर्की (BC) मॉडल से आन्ध्र प्रदेश को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2009-10 में कारबार संपर्कियों द्वारा सम्पूर्ण भारत में खोले गए 7.5 मिलियन नये खातों में से 75% आन्ध्र प्रदेश में हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में परिचालन करेंगी

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की सभी शाखाएं अब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के जमाकर्ताओं सहित सभी ग्राहकों को 27 अगस्त, 2010 से उनके खातों को भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के खातों के रूप में परिचालित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ राजस्थान के आईसीआईसीआईबैंक में विलयन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ राजस्थान (BoR) के आईसीआईसीआई बैंक में विलयन को मंजूरी प्रदान कर दी है। बैंक ऑफ राजस्थान के आईसीआईसीआई बैंक के साथ समामेलन की योजना को स्वीकृति मिलने के उपरांत बैंक ऑफ राजस्थान की सभी शाखाओं ने 13 अगस्त, 2010 से आईसीआईसीआई बैंक की शाखाओं के रूप में काम करना आरंभ कर दिया है। बैंक ऑफ राजस्थान की 468 शाखाओं के जुड़ जाने के परिणामस्वरूप आईसीआईसीआई बैंक का शाखा नेटवर्क बढ़कर 2,484 तक पहुंच गया है।

क्रेडिट सुइस को मुंबई में शाखा खोलने का लाइसेंस मिला

क्रेडिट सुइस को मुंबई में एक शाखा खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। उक्त अनुमति प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप क्रेडिट सुइस अपनी सेवाओं की श्रृंखला को भारतीय बाज़ार तक विस्तारित करने में समर्थ हो गया है। उक्त शाखा जमाराशियां स्वीकार करेगी तथा अपने तुलन पत्र का उपयोग भारत में क्रेडिट सुइस की गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की सक्षमताओं को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को वित्तीयन उपलब्ध कराने में करेगी। उक्त लाइसेंस बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य घरेलू नियत आय उत्पादों एवं विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने में समार्थ बनाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित : भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट

तालिका के अनुसार भुगतान करने के लिए (कागज़ के स्थान पर) इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग में पिछले तीन वर्षों में तीव्र वृद्धि देखने में आई है। मूल्य की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का अंश वर्ष 2007-08 के 80.4 % से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 88.3% हो गया है।

कागज़ पर आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का अंश

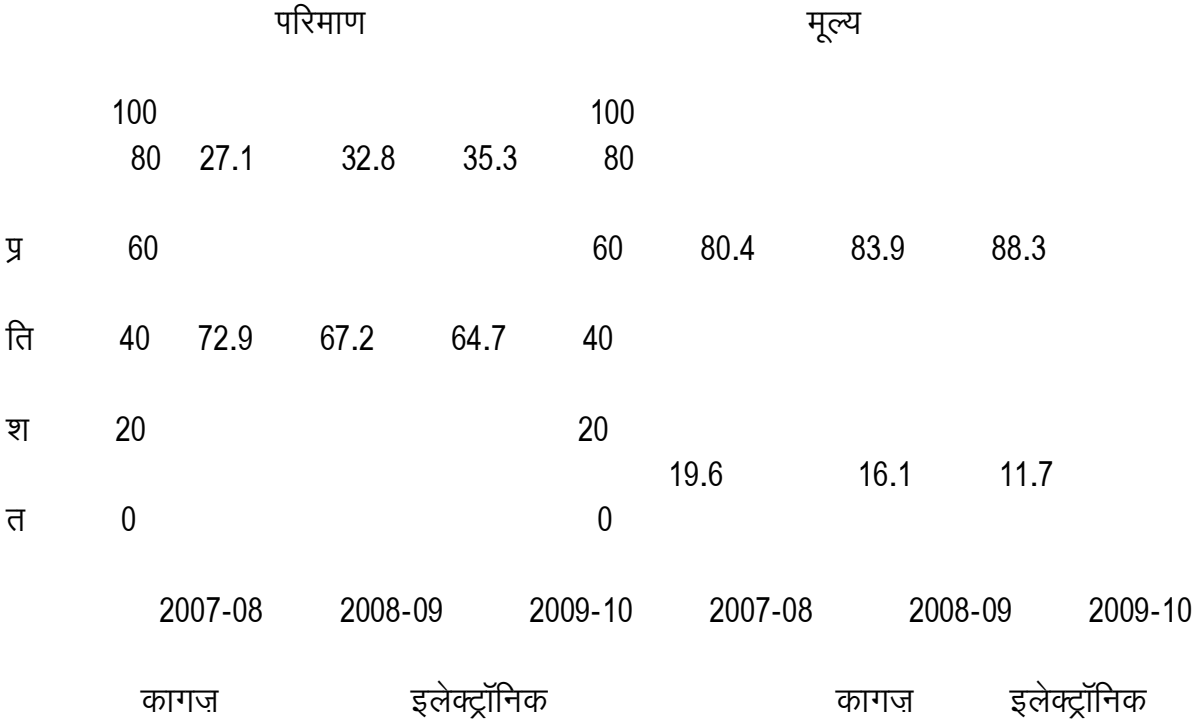

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां एवं घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याजगत आर्थिक सहायता योजना विस्तारित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कपड़ों, हस्तशिल्प, चर्मोत्पाद विनिर्माताओं, जूट एवं इंजीनियरिंग सामानों के विनिर्माताओं जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों को रुपया निर्यात ऋण पर 2% की ब्याजगत आर्थिक सहायता को विस्तारित कर दिया है। अब यह योजना 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक उपलब्ध हो गई है। बैंकों से रुपया निर्यात ऋण अग्रिमों की सभी अवधियों की उनकी प्रयोज्य ब्याज दरों को नये अग्रिमों के सम्बन्ध में 7% की न्यूनतम नियत दर की शर्त पर आधार दरों से सम्बद्ध करने के लिए कहा गया है। उक्त योजना नवम्बर, 2008 में प्रारंभ की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस हेतु 18 विदेशी बैंकों के आवेदनों पर कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक उन 18 विदेशी बैंकों के आवेदनों पर कार्रवाई कर रहा है, जो भारत में शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय खोलना चाहते हैं। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीना ने कहा कि "30 जून, 2010 के दिन देश में विदेशी बैंकों की 300 से अधिक शाखाएं मौजूद थीं।" इस आशय के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या इस प्रवृत्ति से घरेलू बैंक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, मंत्री महोदय ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक इसके प्रभाव पर एक विचार-विमर्श दस्तावेज़ तैयार कर रहा है तथा इन बैंकों को नये लाइसेंस प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में अंतिम सिफारिशें तैयार किए जाने में कुछ समय लगेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने प्रसार-क्षेत्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का उत्सुक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन योजना के तहत विकसित किए गए अपने प्रसार-क्षेत्र कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाने के प्रति उत्सुक है। उक्त कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उनके बच्चों को शिक्षित किए जाने, बचत करने की आदत विकसित किए जाने और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए उनकी अपेक्षाओं और जरूरतों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना तथा दूर-दराज़ के खेड़ों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है।

ऋण चूक अदला-बदली की अनुमति केवल कारपोरेट बॉण्डों पर ही होगी- भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि ऋण चूक अदला-बदली (CDS) बाज़ार का विकास अंशाकित और व्यवस्थित रूप में होना चाहिए, जिसमें वास्तविक ध्यान संपदा क्षेत्र की सहलग्नताओं पर होना चाहिए तथा हाल ही के वित्तीय संकट के दौरान यथा-परिलक्षित विविध प्रकार के जोखिमों से निपटने के लिए सुदृढ़ जोखिम प्रबन्धन संरचना के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व वैंक ने निवासी कम्पनियों के लिए उपयुक्त सुरक्षोपायों की शर्त पर प्लेन वनीला काउंटर पर विक्रेय एकल - नाम वाली ऋण चूक अदला-बदली व्यवस्था प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्तावित था कि प्रारंभ में ऋण चूक अदला-बदली से सम्बन्धित सभी लेन-देनों की रिपोर्टिंग एक केन्द्रीकृत रिपोर्टिंग मंच को की जानी चाहिए और कुछ समय के बाद उन्हें एक केन्द्रीय समाशोधन मंच पर लाया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूति पोर्टफोलियो के मानदंड परिवर्तित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा था कि परिपक्वता तक धारित HTM) श्रेणी वाली प्रतिभूतियों में/से बिक्री एवं हस्तांतरण का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में परिपक्वता तक धारित श्रेणी में धारित निवेशों के बही-मूल्य से 5% अधिक हो जाने पर बैंक को परिपक्वता तक धारित श्रेणी में किए गए निवेशों के बाज़ार मूल्य पर विचार-विमर्श करना चाहिए। इसके अलावा यह भी कि इससे उस बाज़ार मूल्य, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, की तुलना में बही-मूल्य की अधिकता का भी पता चलना चाहिए। यह प्रकटन बैंकों के लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखा-टिप्पणियों' में किया जाना अपेक्षित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को मुद्रा वायदों में लेन-देन की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को उनके अन्तर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिमों (एक्सपोजरों) को प्रतिरक्षित करने के प्रयोजन हेतु केवल शेयर बाज़ारों के माध्यम से मुद्रा वायदा सौदों में सहभागिता करने की अनुमति प्रदान की है। अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां सभी चारों युग्मों - अमरीकी डालर - रुपया, पौंड स्टर्लिंग - रुपया, जापानी येन - रुपया और यूरो - रुपया में मुद्रा वायदा सौंदे कर सकती हैं। राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) ने पहली बार अगस्त, 2008 में वायदा सौदों में लेन-देन करना आरंभ किया था। जब वर्ष 2008 में डालर - रुपया युग्म में मुद्रा वायदा सौदों की शुरूआत की गई थी, तो एक उत्पाद के रूप में उसे भारी सफलता प्राप्त हुई थी, जिसमें दैनिक आवर्त लगभग 5.2 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 240 करोड़ रुपये) था। किन्तु अन्य युग्मों में लेन-देन को डालर - रुपया युग्म जितनी अच्छी सफलता नहीं मिली थी। यह देखा जाना शेष है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बाज़ार में उतरने के परिणामस्वरूप दैनिक लेन-देन में परिमाण में बढ़ोत्तरी कैसे होगी।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों के सम्बन्ध में बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का फरमान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि तत्काल सकल भुगतान (RTGS), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (NECS) और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ECS) स्वीकार्यता और व्याप्ति क्षेत्र की दृष्टि से विकसित हो रही हैं। इस प्रकार यह आवश्यक है कि सदस्य बैंक इन प्रणालियों की विश्वसनीयता को बनाए रखें तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करें। सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली जमाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर गंतव्य खाता धारकों को प्रदान कर दें। विधिमान्य कारणों से जमा प्रदान करना संभव न होने की स्थिति में इस प्रकार की रकमों को निर्धारित कार्यविधि के अनुसार वापस कर दिया जाना है।

बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों के लिए खुदरा लेन-देन मंच का अध्ययन करने हेतु कहा गया

सरकारी प्रतिभूति (G-sec) बाज़ारं में खुदरा निवेशकों की रुचि पुनर्जागृत करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से इन प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को एक अलग लेन-देन मंच के माध्यम से सुगम बनाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा है। प्रत्यक्ष रूप से खुदरा निवेशकों के लिए बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़े एक अलग ऑनलाइन लेन-देन मंच का विचार प्रतिपादित किया गया है, ताकि सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेनों को सीवन-रहित (किसी जोड़ के बिना) निष्पादित किया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक की आय में कमी आई

भारतीय रिज़र्व बैंक की कुल वार्षिक आय में लगभग 46% की गिरावट आ गई है, जो जुलाई 2009 में 60,732 करोड़ रुपये से घट कर जून 2010 में 32,884 करोड़ रुपये रह गई है। इस गिरावट का कारण विदेशी स्रोतों से आय में हुई 51% की कमी थी, जो कम हो कर 25,103 करोड़ रुपये तथा घरेलू स्रोतों से आय में हुई 22% की गिरावट थी, जो कम हो कर 7,782 करोड़ रुपये रह गई। निवल ब्याजगत आय में मुख्यत: प्रतिफलों में आई तीव्र कमी के कारण 46.96% की गिरावट आई, जिससे वह घट कर 31,747 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई। बैंक नोटों की अधिप्राप्ति में हुई 24.7% की वृद्धि के कारण कुल व्यय 2.25% की बढ़ोत्तरी के साथ 8,403.12 करोड़ हो गया। फलत: आय की तुलना में लागत अनुपात लगभग दोगुना बढ़ कर 14% से 26% हो गया।

विदेशी मुद्रा अनाश्रयता (एक्सपोजर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से उनके कारपोरेट ग्राहकों की अप्रतिरक्षित (unhedged) विदेशी मुद्रा अनाश्रयता (एक्सपोजर) से सम्बन्धित जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करने के लिए कहा है। वर्ष 2009-10 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय बैंक का कहना है कि विनिमय दरों में होने वाले प्रतिकूल

उतार-चढ़ावों के कारण कुछेक बैंक उधारकर्ता प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, उसे पुनर्संरचित आस्तियों से चूक (delinquency) में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होने की आशा नहीं थी। वर्ष 2008 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पुनर्संरचित आस्तियों को मानक आस्तियां मानने की अनुमति प्रदान की थी - जो वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बैंकों को दिए गए एकबारगी अपमार्ग के रूप में था। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पुनर्संरचित अग्रिमों में 31 मार्च को कुल सकल अग्रिमों के 3% का समावेश था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को लाभप्रदता और आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट के प्रति भी आगाह किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि "आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली के तुलन पत्र की वृद्धि में कमी आई है। इसका ऋण की गुणवत्ता ओर लाभप्रदता पर मंद प्रभाव हो सकता है। कुछेक ऐसे खातों में, जिन्हें विशेष व्यवस्था के तहत पुनर्संरचित किया गया था, फिसलन होने पर आस्ति की गुणवत्ता कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है।" उसका यह भी कहना है कि "जहां ऋण एवं ब्याज दर आघात के प्रति वाणिज्यिक बैंकों के लचीलपन में पिछले कुछ समय से बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं चलनिधि परिदृश्य के विश्लेषण से कुछ संभाव्य जोखिम का पता चलता है। निवेश संविभाग पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किए जाने के प्रभाव, वर्धित प्रावधानीकरण सम्बन्धी अपेक्षाओं तथा बचत खातों से सम्बन्धित ब्याज दरों की दैनिक आधार पर गणना से बैंक मार्जिनों को दबाव का सामना करना पड़ सकता है।" मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर बनाने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों के साथ ही चलनिधि की कठोर स्थितियों के बीच सरकारी बॉण्डों पर प्रतिफल में वृद्धि हो रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अनर्जक आस्तियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रावधान करने तथा इस वर्ष के सितम्बर माह तक 70% प्रावधानीकरण व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कहा है। यद्यपि अधिकांश बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य बनाए गए मानदंडों को पूरा कर चुके हैं, कुछेक अपेक्षाकृत बड़े बैंकों ने इसे बढ़ाए जाने की मांग की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घट कर 82 हुई - भारतीय रिज़र्व बैंक

सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आरंभ की गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के समामेलन की प्रक्रिया के अनुसरण में मार्च, 2010 के अंत में उनकी कुल संख्या 82 रह गई है। वर्ष 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ एवं समेकित करने के उद्देश्य से सरकार ने चरणबद्ध रीति से उनके समामेलन की प्रक्रिया आरंभ की थी। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 से घट कर 31 मार्च, 2010 के दिन 82 रह गई है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

वर्ष 2009-10 में अल्पसंख्यकों को उधार देने में बैंक लक्ष्य से पीछे

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) वर्ष 2009-10 में अल्पसंख्यक वर्गों को उधार देने के अपने लक्ष्य से पीछे रह गए। उसमें भी उत्तर-पूर्वी राज्यों, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों की तुलना में गुजरात, महाराष्ट्र, और दिल्ली जैसे समृद्ध राज्यों में उधार देने का स्तर

अत्यधिक कम रहा। सरकारी नियमों के अनुसार बैंकों से मार्च, 2010 में समाप्त वर्ष में लगभग 15% प्राथमिकता प्राप्त ऋण अल्पसंख्यकों को देना अपेक्षित था, किन्तु वे केवल 13% ही ऋण दे सके।

कुल भुगतान और निपटान आवर्त में 15.6% की वृद्धि

विभिन्न प्रकार की भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के तहत कुल आवर्त में मूल्य की दृष्टि से वर्ष 2008-09 के 13.3% की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान 15.6% की वृद्धि दर्ज हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 30 जून, 2010 तक 40 बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किए जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 09 में ऋण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की हिस्सेदारी 50.5% रही

भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा वर्ष 2008-09 में दिए गए कुल 14,36,769 करोड रुपये के ऋणों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का हिस्सा 50.5% रहा।

बैंकों की पूंजी वृद्धि वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित रैंकिंग पर आश्रित होगी

बैंकों में पूंजी वृद्धि इस बात के फलन का भी काम कर सकती है कि वे वित्तीय समावेशन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के प्रति कितने गंभीर हैं। वित्त मंत्रालय बैंकों का क्रम - निर्धारण वित्तीय समावेशन के सूचकांक के आधार पर करेगा तथा उसका उपयोग उन्हें नयी पूंजी उपलब्ध कराने के समय एक मानदंड के रूप में करेगा। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में स्वयं बैंकों के कार्य-निष्पादन के श्रेणी-निर्धारण को शामिल किए जाने हेतु शीघ्र ही आरंभ किए जाने वाले वित्तीय समावेशन सूचकांक के दायरे को विस्तारित किया जाएगा। मूल रूप से उक्त सूचकांक का उद्दिष्ट वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के आधार पर विविध भौगोलिक क्षेत्रों का क्रम निर्धारण करना था।

बैंकों ने निवल लाभ में 26.5% की वृद्धि दर्ज की

39 (शेयर बाज़ार की सूची में) सूचीबद्ध उधारदाताओं की अप्रैल - जून तिमाही की निवल ब्याजगत आय (NII) और निवल लाभ की संख्याएं देखने पर ऐसा लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में संवेग (momentum) आता दिखाई दे रहा है। सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा दर्ज 20% से अधिक की ऋण वृद्धि तथा जमा लागत में 100 से अधिक आधार अंकों (bps) की गिरावट के फलस्वरूप सूचीबद्ध बैंकों ने निवल ब्याजगत आय में 46.5% के रूप में अब तक सर्वोत्तम तिमाही वृद्धि दर्ज की है।अन्य आय में 14.5% गिरावट आने तथा प्रावधानों और आकस्मिकताओं मे 39% की वृद्धि हो जाने के कारण निवल लाभ मे 26.45% की अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि दर्ज हुई।

नयी जमाराशियों, सरकारी खर्चों के आधार पर बैंकों की चलनिधि में बढ़ोत्तरी

हाल के दिनों में बैंकों ने चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पुनर्खरीद पटल से उधार नहीं लिया है। वास्तव में वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पुनर्खरीद पटल के माध्यम से 2500 करोड़ रुपये तक की सीमा तक निधियां रखते रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय रिज़र्व बैंक ने औसतन दैनिक आधार पर जुलाई में 34,000 करोड़ रुपये और जून में 47,000 करोड़ रुपये अन्त:क्षेपित किया था। एक ऐसी स्थिति, जिसमें बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेते रहे हैं, से अचानक अधिशेष नकदी के रूप में आया यह बदलाव मुख्यत: सरकारी खर्चों, बैंकों द्वारा जमाराशियां जुटाए जाने तथा इक्विटी बाज़ार में पूंजी के अन्तर्वाह के कारण संभव हुआ है।

देना बैंक 800 कारबार संपर्की नियुक्त करेगा

देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री डी.एल. रावल द्वारा यथापुष्ट समाचार के अनुसार उक्त बैंक 1,800 गांवों में 800 बैंकिंग कारबार संपर्की नियुक्त करने हेतु तत्पर है। 'कारबार संपर्की' लघु व्यवसायी या व्यक्ति होते हैं, जिनका उपयोग बैंक-रहित क्षेत्रों में बैंक की ओर से मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु किया जाता है।

अवसर की ताक में क्रेडिट ब्यूरो के बीच आपा-धापी

बैंकों को शीघ्र ही उनकी सूचना के स्रोत का चयन करने के अधिकाधिक विकल्प प्राप्त होंगे, क्योंकि अधिकअधिक क्रेडिट ब्यूरो चीन के बाद अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में वित्तीय उत्पादों के प्रयोक्ताओं की बढ़ती संख्या में हिस्सेदारी करना चाहते है।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक लाभार्जन हेतु प्रतिभूतिकरण के विरुद्ध

भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (NBFCs) प्रतिभूतिकरण का कार्य केवल जोखिम हस्तांतरण के लिए करें न कि लाभार्जन के लिए। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर सुश्री श्यामला गोपीनाथ का साग्रह कथन है कि शीर्ष बैंक स्थिर प्रतिभूतिकरण की व्यवस्था चाहता है। "हम बाज़ारों का विकास अंतरपणन के आधार पर नहीं होने दे सकते। हमें प्रतिभूतिकरण की जरूरत है; हमारे लिए बैंक की आस्तियों को अर्थसुलभ बनाना आवश्यक है। किन्तु उस स्थिति में इसे वास्तविक जोखिम हस्तांतरण बनना होगा। यदि ऋण वृद्धि ही अतिशय है, तो यह जोखिम का वास्तविक हस्तांतरण नहीं है।"

प्रतिभूतिकरण से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रतिभूतिकरण से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को अप्रैल में जारी उनके प्ररूप पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से प्रति-सूचना प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही अंतिम रूप देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर सुश्री श्यामला गोपीनाथ का कहना है कि "प्रारंभ में हमने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से प्रति-सूचना नहीं मंगवाई थी, किन्तु बाद में हमने उनसे भी प्रति-सूचना मंगवाई है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने यह कहते हुए कि उनके ऋण अल्पावधिक होते हैं तथा उनकी वसूली की पद्धति भी भिन्न होती है, एक अलग प्रकार के सलूक की मांग की है।"

मोटर पूल को समाप्त करने के बारे में इर्डा "पूर्वाग्रहमुक्त" है

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरिनारायण द्वारा इस आशय के एक प्रश्न कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियां 'वाणिज्यिक साधन के रूप में अन्य पक्षकार' जोखिमों की हामीदारी देने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, 'मोटर पूल' व्यवस्था को समाप्त करने का समय आ गया है, के प्रत्युत्तर में दिए गए बयान के अनुसार इर्डा 'मोटर पूल. व्यवस्था की समाप्ति के मुद्दे पर 'पूर्वाग्रहमुक्त' है।

भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पत्रों (CPs) की गुणवत्ता के बारे में चिंतित, नियमों को संशोधित करेगा

वाणिज्यिक पत्रों के निर्गमों की संख्या में उफान आ जाने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन दस्तावेज़ों में निहित साख की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर सुश्री श्यामला गोपीनाथ का कहना है कि "हम वाणिज्यिक पत्रों के निर्गमों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को संशोधित करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तथा इस मामले पर बाज़ार के सहभागियों के साथ चर्चा करना चाहेंगे।" हम चाहते हैं कि केवल श्रेणी-निर्धारित (rated) वाणिज्यिक पत्र ही जारी किए जाएं। सुश्री गोपीनाथ का कहना है कि आधार दरों में कमी आने के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक पत्रों के निर्गमों में बढ़ोत्तरी होना अवश्यंभावी है। इसके अलावा, यह अच्छी बात है कि बैंक इन वाणिज्यिक पत्रों में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यह बाज़ार का लिखत है तथा कारपोरेट कम्पनियां वाणिज्यिक पत्रों के बाज़ारों तक सीधे ही पहुंच सकती हैं। हाल के महीनों में वाणिज्यिक पत्र अल्पावधिक निधियां जुटाने के लिए पसंदगी वाले लिखत बन गए हैं, क्योंकि वे उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को आधार दर से कम दर पर उधार न देने से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक की बाध्यताओं की अनदेखी करने की सुविधा प्रदान करते हैं। निर्गमों की रकम अप्रैल में 83,165 करोड़ रूपये से बढ़ कर जुलाई के पहले पखवाड़े में 1,07,755 करोड़ रुपये हो गई है, क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में आधार दरों में कमी आ गई थी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पर्यवेक्षण में तेजी लाई जानी आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक अन्तर्निहित जोखिमों के अधिक सख्त निर्धारण के लिए गैर-बैंकिंग कम्पनियों की पर्यवेक्षी प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता महसूस करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2009-10 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि "(नये) उत्पादों और बाज़ारों का विकास करते समय मुख्य बुनियादें (underpinnings) यह सुनिश्चित करने में समर्थ होंगी कि बैंकों से परे अमध्यस्थीकरण की प्रक्रिया प्रामाणिक है और ऐसे क्षेत्रों में जहां बैंक और गैर-बैंकिंग कम्पनियां, दोनों ही कार्यरत हैं, वहां जोखिमों का एक विवेकसम्मत ढांचे में सुस्पष्ट एवं पारदर्शी विधि से पता लगा लिया जाता है।" जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के किसी भी समामेलन या विलयन के लिए अब भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होता है। इसके अलावा, विलयित कम्पनी के प्रबन्धन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के "सुयोग्य एवं उपयुक्त" मानदंडों का पालन करना आवश्यक होता है।

सूक्ष्मवित्त

स्वयं सहायता समूह - बैंक सहलग्नता कार्यक्रम (SBLP) का मात्रात्मक कार्य-निष्पादन

(रकम करोड़ रुपयों में)

मानदंड		2006-07	2007-08	2008-09
स्वयं सहायता समूहों की बचतें	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	4160584	5009794 (20.4%)	6121147 (22.2%)
	रकम	3512.71	3785.39 (7.8%)	5545.62 (40.5%)
बैंक ऋण का संवितरण	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	1105749	1227770 (11%)	1609586 (31.1%)
	रकम	6570.69	8849.26 (34.7%)	12253.51 (38.5%)
बकाया बैंक ऋण	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	2894505	3625941 (25.3%)	4224338 (16.5%)
	रकम	12366.49	166999.91 (37.5%)	22679.84 (33.4%)

स्रोत : भारत माइक्रोफाइनैंस रिपोर्ट साइड बाई साइड 2009

विदेशी मुद्रा विनिमय

अस्थिर पूंजी प्रवाह बढ़ कर विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि का 58% हुआ

संचयी पोर्टफोलियों अन्तर्वाहों और देश की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि की तुलना में अल्पावधिक ऋण को शामिल करने हेतु निर्धारित अस्थिर पूंजी प्रवाहों का अनुपात पिछले वर्ष के 47.9% की तुलना में मार्च, 2010 में बढ़ कर 58.1% हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि की तुलना में अल्पावधिक ऋण का अनुपात मार्च, 1991 के 146.5% से घट कर मार्च, 2005 में 12.5% हो गया, किन्तु वर्ष 2006 में बढ़ कर 12.9% के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, अल्पावधिक ऋणों के औसत में विस्तार के परिणामस्वरूप उक्त अनुपात मार्च, 2008 के 14.8% से बढ़ कर मार्च, 2009 में 17.2% और मार्च, 2010 में 18.8% हो गया।

सितम्बर, 2010माह के लिए लागू विमुअनि (बैंक)/ अनिवि
जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवि जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली (स्वैप दरें)

मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली		
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	
अमरीकी डालर	0.84306	0.6650	0.9490	

विमुअनि (बैंक) जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली (स्वैप दरें)

मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.84300	0.665	0.949	1.270	1.572
ब्रिटिश पौण्ड	1.46266	1.2340	1.5050	1.7850	2.0400
यूरो	1.38688	1.259	1.394	1.563	1.732
जापानी येन	0.66875	0.416	0.435	0.468	0.521
कनाडाई डालर	1.87167	1.342	1.564	1.806	2.039
आस्ट्रेलियाई डालर	5.41750	4.670	4.710	4.890	4.980

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि

मद	20 अगस्त, 2010 के दिन	20 अगस्त, 2010 के दिन
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3
कुल आरक्षित निधियां	13,15,884	282,549
क) विदेशी मुद्रा में आस्तियां	11,94,167	256,369
ख) सोना	89,564	19,278
ग) विशेष आहरण अधिकार	23,157	4,971
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधि की स्थिति	8,996	1,931

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

बीमा

परम्परागत उत्पादों पर प्रभारों पर रोक लगाने की कोई योजना नहीं : इर्डा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा परम्परागत उत्पादों पर वसूल किए जाने वाले प्रभारों पर रोक लगाने की कोई योजना नहीं है। विनियामक ने इस बात के प्रति भी आश्वस्त किया है कि वह नयी यूनिट सम्बद्ध योजनाओं (यूलिप्स) को समय पर अनुमोदित कर देगा, ताकि बीमाकर्ता उन्हें 1 सितम्बर और उसके बाद बेच सकें।

न्यू इंडिया बैंकिंग संपर्कियों का उपयोग करने का इच्छुक

न्यू इंडिया अश्योरेंस ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि उसे और समस्त बीमा कम्पनियों को कारबार संपर्कियों का उपयोग बीमा क्षेत्र की भी सेवा करने हेतु करने की अनुमति दी जाए। कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम. रामदास द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन के अनुसार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी - न्यू इंडिया अश्योरेंस ने सूक्ष्म बीमा क्षेत्र में निहित विशाल लाभप्रदता के कारण व्यापक पैमाने पर सूक्ष्म बीमा करने की योजना बना रखी है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें बीमे को बेचने (और सेवा प्रदान करने) हेतु बैंकिंग कारबार संपर्कियों के उपयोग को महत्व प्राप्त हो जाता है।

अन्तरराष्ट्रीय समाचार

बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) द्वारा बॉण्ड प्रोत्साहन अभियान जारी

बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) द्वारा अपनी बॉण्ड प्रोत्साहन योजना जारी रखी गई है और अपनी न्यूनतम ब्याज दरों को रिकार्ड कम स्तर पर रखा गया है, क्योंकि अधिकारियों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े बजट संकुचन के दौरान अर्थव्यवस्था के लिए आकस्मिक सहायता जारी रखी है। गवर्नर श्री मर्विन किंग के नेतृत्व वाली नौ सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने बॉण्ड धारिता का लक्ष्य 200 बिलियन पौण्ड (318 बिलियन अमरीकी डालर) नियत किया है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE), यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ECB) ने दरें अपरिवर्तित रखीं

बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) ने वृद्धि दर में हाल की बढ़ोत्तरी के बावजूद ब्रिटेन में नयी मंदी और बढ़ती मुद्रस्फीति के भय के बीच अपनी प्रमुख ब्याज दरों को 0.50% के रिकार्ड कम स्तर पर पर कायम रखी है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित निधियों पर 0.5% की दर पर भुगतान की जाने वाली आधिकारिक बैंक दर को बनाए रखने का निर्णय किया है। बैंक ने अपनी उस मात्रात्मक सहूलियत नीति को परिवर्तित किए जाने के विरुद्ध सहमति व्यक्त की है, जिसके तहत उसने अर्थव्यवस्था कों 200 बिलियन पौण्ड की नयी मुद्रा उपलब्ध कराई है। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों को 1.0% के रिकार्ड निम्न स्तर पर रखा है। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक ने सीमान्त उधार दरों और जमा दरों को भी क्रमश: 1.75% और 0.25% पर अपरिवर्तित रखा है।

अशोध्य ऋणों में गिरावट के कारण यूरोपीय बैंकों को संकट की आशंका

नये बैंकिंग विनियमों के प्रति चिंता और अस्थिर आर्थिक पुनरुत्थान ने यूरोप के अधिकांश शीर्ष बैंकों की ओर से अच्छे परिणामों से सम्बन्धित आशावाद को मंद कर दिया है। घटते अशोध्य ऋणों के कारण परिणामों में अधिकांशतया आशा से अधिक लाभ परिलक्षित होते हैं। ग्रीस के आर्थिक संकट के बाद अशोध्य ऋणों में आशा से भी तीव्र गिरावटें निवेश बैंकिंग से होने वाली आय को पीछे छोड़ रही हैं, जो पिछली तिमाही की उस स्थिति के ठीक विपरीत है जब निवेश बैंकिंग से रिकार्ड परिणाम आए थे। विश्लेषकों का कहना है कि अशोध्य ऋणों में गिरावट अच्छी खबर थी, किन्तु वे इसके बजाय लाभों को राजस्व में बढ़ोत्तरी से प्रेरित होते देखना चाहते हैं।

नई नियुक्तियां

फेडरल बैंक को नया प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मिला

श्री श्याम श्रीनिवासन दि फेडरल बैंक लिमिटेड के नये प्रबन्ध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे।

श्री सोमसुंदरम ने लक्ष्मी विलास बैंक में कार्यभार संभाला

श्री पी.आर. सोमसुंदरम को दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का प्रबन्ध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

बैंकों ने आधार के लिए यूआईडीएआई के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए

इंडियन बैंक और कारपोरेशन बैंक ने भारतीय अनूठे पहचान पत्र प्राधिकरण (UIDAI) की मुख्य परियोजना, आधार के लिए पंजीयक (Registrar) के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। तदनुसार, बैंक अनूठे पहचान पत्र मानदंडों के अनुसार जीवसांख्यिकीय और जनसांख्यिकीय विवरण एकत्रित करते हुए 16 अंकों वाले अनूठे पहचान पत्र जारी किए जाने हेतु ग्राहकों के नाम दर्ज करेंगे।

पीएनबी की दुनिया की सैर और प्लैटिनम डेबिट कार्ड

पंजाब नैशनल बैंक ने ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए मास्टरकार्ड के सहयोग से दो नये उत्पादों यथा - दुनिया की सैर और प्लैटिनम डेबिट कार्ड की शुरूआत की है।

स्टैनचार्ट की सुविधा

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने उभरते समृद्ध (धनवान) वर्ग के लिए अधिमानी बैंकिंग सुविधा की शुरूआत की है। उक्त सुविधा में पुरस्कार कार्यक्रम के साथ बचत, उधार, संरक्षण और निवेश का संयोजन (मिला-जुला रूप) उपलब्ध कराया जाता है।

यूनाइटेड बैंक ने अशौक लेलैंड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने वाणिज्यिक वाहनों के एक अग्रणी विनिर्माता अशोक लेलैंड लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। यूनाइटेड बैंक अशोक लेलैंड के पात्र ग्राहकों को कम्पनी द्वारा विनिर्मित किए जा रहे विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए वित्त प्रदान करेगा।

विजया बैंक ने टोयोटा किर्लोस्कर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

विजया बैंक ने अपनी वाहन - वित्तीयन गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

डीएसपीबीआर सूक्ष्म वित्त ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की

डीएसपी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट के प्रबन्धकों ने खुदरा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की अपनी रणनीति के एक अंग के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक वितरण करार हस्ताक्षरित कयिा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सम्पूर्ण देश में फैली हुई अपनी शाखाओं के माध्यम से डीएसपीबीआर सूक्ष्म वित्त की योजनाओं को वितरित करेगा।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

फाइव अगेन्स्ट बॉण्ड स्प्रेड - एफएबी

पांच वर्षीय खज़ाना बॉण्डों और दीर्घावधिक (15-30 वर्षीय) खज़ाना बॉण्डों के लिए वायदा संविदाओं में समायोजन (offsetting) की स्थिति अपना कर वायदा सौदा बाज़ार में सृजित एक अन्तर। फाइव अगेन्स्ट बॉण्ड अन्तर या तो पांच वर्षीय खज़ाना बॉण्डों के सम्बन्ध में वायदा संविदा को खरीद कर और किसी दीर्घावधिक खज़ाना बॉण्ड बेच कर या फिर उसके विपरीत क्रम द्वारा सृजित किया जाता है। ब्याज दरें उतार-चढ़ावों पर सट्टेबाजी करने वाले निवेशक न्यून अथवा अधि-मूल्य पर मूल्य-निर्धारित खज़ाना बिलों की प्रत्याशा में इस प्रकार के अन्तर का करार करेंगे।

शब्दावली

मोटर पूल

'मोटर पूल' व्यवस्था समस्त 'वाणिज्यक वाहन अन्य पक्षकार क्षति' प्रीमियमों को पूल में संग्रहीत करती है तथा प्रीमियमों की तुलना में दावों के आधिक्य की रकम को एक सूत्र के अनुसार देश की समस्त सामान्य बीमा कम्पनियों में वितरित कर देती है। चूंकि कुल दावे हमेशा संग्रहीत कुल प्रीमियमों से अधिक रहे हैं, सभी कम्पनियों को इस बात पर ध्यान दिए बिना पूल हानियां वहन करनी होती हैं कि उन्होंने वाणिज्यिक वाहन एवं अन्य पक्षकार क्षति जोखिमों की हामीदारी की है अथवा नहीं।

ऋण चूक (व्यतिक्रम) अदला-बदली

पक्षकारों के बीच नियत आय वाले उत्पादों के ऋण जोखिम को हस्तांरित करने हेतु तैयार किया गया एक अदला-बदली (स्वैप) उत्पाद। किसी ऋण अदला-बदली के क्रेता को ऋण संरक्षण प्राप्त होता है, जबकि उक्त अदला-बदली का विक्रेता उक्त उत्पाद की ऋणपात्रता (creditworthiness) की गारंटी देता है। ऐसा करते हुए चूक (व्यतिक्रम) जोखिम को नियत आय वाली प्रतिभूति के धारक से अदला-बदली के विक्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी ऋण अदला-बदली का क्रेता बॉण्ड के कूपन भुगतान में चूक किए जाने पर उस अदला-बदली के विक्रेता द्वारा उस बॉण्ड के सम मूल्य का पात्र होता है।

संस्थान समाचार

सीएआईआईबी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

संस्थान इसके पूर्व यथा-घोषित रूप में दिसम्बर, 2010 और उसके बाद से सीएआईआईबी परीक्षा के आशोधित विन्यास की शुरूआत करेगा। (अधिक विवरण के लिए http://www.iibf.org.in देखें)।

सीएआईआईबी (2010) के लिए संशोधित अध्ययन सामग्री

सीएआईआईबी के लिए अध्ययन सामग्री मैकमिलन इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जा रही है। (अधिक विवरण के लिए http://www.iibf.org.in देखें)।

ऋण वसूली एजेन्ट पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यसामग्री

"हैंडबुक ऑन डेट रिकवरी" अंग्रेजी के अलावा निम्नलिखित भाषाओं में भी उपलब्ध है : यथा - असमी, बंगाली, हिन्दी, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल।

आभासी कक्षाएं

संस्थान ने आगामी जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आभासी कक्षाओं (**सक्रिय** अन्योन्य-क्रिया सम्बन्धी (Interactive) शिक्षण) की व्यवस्था कर रखी है। अधिक विवरण के लिए कृपया http:// www.iibf.org.in देखें।

परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

आईएमएफआर चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का 12वां बैच 22 नवम्बर, 2010 से 27 नवम्बर, 2010 तक संचालित किया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया http:// www.iibf.org.in देखें।

संपर्क कक्षाएं

आंचलिक कार्यालयों द्वारा आगामी जेएआईआईबी / सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए संपर्क कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया http:// www.iibf.org.in देखें तथा आंचलिक कार्यालयों से संपर्क करें।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

सिंडिकेट बैंक के लिए कारबार सपर्कियों / कारबार सुसाधकों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन 5 और 6 सितम्बर, 2010 को बेंगलूर में किया गया और एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन देना बैंक के लिए 20 और 21 सितम्बर, 2010 को अहमदाबाद में किया जाएगा।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए जोखिम आसूचना पर विशेष कार्यक्रम

संस्थान द्वारा डेलोइट के सहयोग से 20 अगस्त, 2010 को जोखिम आसूचना पर एक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई। इसमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 20 वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम ने बैंकों के समक्ष उपस्थित होने वाले जोखिमों के विविध आयामों से सम्बन्धित अन्तर्दृष्टि उपलब्ध कराई।

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम

हैदराबाद में आयोजित होने वाले उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम के पहले बैच की शुरूआत 4 अक्तूबर, 2010 से इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (IPE), हैदराबाद में होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया http://www.iibf.org.in देखें ।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दर

6.10
5.90
5.70
5.50
5.30
5.10
4.90
4.70
4.50

02/08/10 04/08/10 05/08/10 09/08/10 11/08/10 14/08/10 16/08/10 21/08/10 23/08/10 24/08/10 27/08/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर्स, अगस्त, 2010

- मांग दरें 4.53 और 5.84 के बीच मंडराती रहीं।

- चलनिधि की स्थिति माह के अंत में सहज हुई।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18500
18400
18300
18200
18100
18000
17900
17800
17700

07/08/10 10/08/10 11/08/10 13/08/10 16/08/10 17/08/10 18/08/10 20/08/10 24/08/10 25/0810 26/08/10 27/08 10 31/08/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर्स, अगस्त, 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर

80
75
70
65
60
55
50
45

02/08/10 04/08/10 05/08/10 06/08/10 09/08/10 11/08/10 12/08/10 13/08/10 16/08/10 18/08/10 24/08/10 25/08/10 27/08/10 31/08/10

पौंड स्टर्लिंग यूरो जापानी येन अमरीकी डालर

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- डालर के समक्ष रुपया में मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।
- 09 अगस्त के दिन सुदृढ़ पोर्टफोलियो प्रवाह की पृष्ठभूमि में मुद्रा में मूल्यवृद्धि - जुलाई के दौरान 3.5 बिलियन डालर - हो रही थी, भारतीय रुपये में 09 अगस्त को लगभग 6 सप्ताह पहले जैसा उछाल आया।
- तेल खरीदने हेतु डालर की खरीद पर रुपया पुन: लुढ़का।
-अंत में माह के दौरान डालर के समक्ष रुपये में 1.92% का मूल्यह्रास हुआ, जिससे वह 47.08 रुपये पर बंद हुआ।
- पौंड-स्टर्लिंग के समक्ष रुपया सामान्य रूप से अनियमित रहा।

विनिमय दर

अमरीकी डालर / भारतीय रुपया नियत एवं अंतिम

47.20
47.00
46.80
46.40
46.20
46.00
45.80
45.60

11.30 पूर्वान्ह
05.00 अपरान्ह

02/08/10 16/08/10 31/08/10

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न सितम्बर, 2010